

officer, recording officer, Inquiry officer, all should be lady officers. Unless that is done, nobody would speak out.

I understand some of the victims have got married and have settled down, they don't want to come forward and say that this had happened with them because if they do that, their personal life is going to be disturbed. Their demand is that if they come forward and give a statement, their identity should not be disclosed. There are two more issues. First as far as the State machinery is concerned and police machinery is concerned, I do not believe in them. Tirupati Hotel and the Police Officers' quarters are just on the opposite side. If I may add further, if the police officers were saying that they did not believe in these things, there are mothers who have stated and have gone on record that they used to carry their daughters to Pandit Sapkale to his house. Wait till work was over and then bring their daughters home. They have complained to the police, but no action has been taken by the police. Therefore, my demand is that the Home Minister should come to this House and state whether there are 500 victims or only 47 victims. There are two officers, who have been fighting against each other. The Inquiry Committee that has been nominated is silent on this point as to how many victims have come and how many have not come. Secondly, the industrial and business lobby involved in it is safe. I would not like to name the officers who have been saved. The conduct of Deswala, the Inquiry Officer, has also got to be checked up. What was he doing on the day when Raju Tadvi was arrested in a case involving an industrialist? Another aspect which has not been investigated and on which we are agitating is the residence of Mr. Pandey. As the Hotel Tirupati was used, the residence of Mr. Pandey was also used for photographing and blue-filming. Nobody knows today whether Mr. Pandey is alive or dead. Pandey is shown as a supplier to the Jain companies. What

has happened to this man? Therefore, the proper thing is that the Home Minister should come over here and give an assurance in this House that if the State police in Maharashtra fails to provide protection to the victims there, the Central Government would give them protection and a proper inquiry would be held.

SHI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman I associate myself with the special mention made by Mr. Ambedkar.

Re. Selling of Sugar Mills to Private Individuals by the Government of Uttar Pradesh

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश...

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) :
गौतम जी जो कह रहे हैं, उस पर मेरा प्वाइंट आफ़ ऑर्डर है। मैं जानता हूँ कि जीरो भावर में प्वाइंट आफ़ ऑर्डर नहीं होता, संसदीय लोकसभा के लिये मैं बहुत नया प्रादमी नहीं हूँ लेकिन माननीय गौतम जी, जो मुझ उठाये जा रहे हैं वह मुझ राज्य सरकार से संबंधित है।

श्री संघ प्रिय गौतम : अभी मैंने उठाया ही कहा है? पहले उठा तो लेने दीजिये।

श्री जनेश्वर मिश्र : बीनी मिलों की बिक्री के सवाल पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बीनी मिलों को बेचा है... (व्यवधान)... आप सुन लें। मैं वैधानिक सवाल उठा रहा हूँ।... (व्यवधान)... शास्त्री जी आप सुन लीजिये।... (व्यवधान)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष जी ने उनको इस पर बोलने की अनुमति दी है उनको बोलने दिया जाए। इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let him finish What he wants to speak.

श्री जनेश्वर मिश्र : वह आप समाप्त नहीं पा रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माधुर (उत्तर प्रदेश) : वह कह रहे हैं कि राज्य का प्रभाव है, इसलिये उसको यहाँ नहीं उठाया जा सकता है लेकिन मेरा कहना है कि... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let me hear him.

श्री जनेश्वर मिश्र : अपने देश का एक सन्निधन है। तो क्या हम लोगों के सदन का यह जीरो आवर उस संविधान की मर्यादा के ऊपर जायेगा? राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह अपने जगलों की लकड़ी बेच सके, वह अपने यहाँ कलेक्टर को नियुक्त कर सके, कोई विश्वविद्यालय बंद कर सके, कोई कारखाना बंद कर सके। राज्य सरकार के रोज रोज के कार्यों पर यह महान सदन बहस करने लगेगा तो वह संविधान का अतिक्रमण होगा या नहीं होगा? व्यवस्था के तौर पर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा—और कौन जवाब देगा इसका? भान सीजिये इन्होंने एक आरोप लगाया किसी वैधानिक कार्य को लेकर, राज्य के मुख्य मंत्री या सरकार की तरफ से उठाये गये कदम को लेकर तो इस सदन में उसकी सफाई देने के लिये कौन आवेगा? मुलायम सिंह यादव तो नहीं आ सकते, वहाँ के मुख्य मंत्री नहीं आ सकते। ... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माधुर : मैं आप को बताना चाहता हूँ कि आप इतने भोलेपन के साथ... (व्यवधान)... आप लोगों ने राजस्थान में हमारी पार्टी की सरकार पर यहाँ आरोप लगाये हैं (व्यवधान)... और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं ... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You are not here to give an answer. I will tackle aim.

श्री जनेश्वर मिश्र : जब तक कोई भ्रमानवीय कार्य और अवैधानिक कार्य न हो—जलगांव कांड भ्रमानवीय था। जब तक भ्रमानवीय और अवैधानिक कार्य किसी प्रदेश में नहीं होता जब तक सदन में उसको नहीं उठाया जा सकता। ये दो मुद्दे हैं। संविधान का अतिक्रमण और भ्रमानवीय कार्य, ये दो कार्य जब तक न हों तब तक क्या ऐसा किया जा सकता है, इस पर आप व्यवस्था देकर फिर भीतम जी और दूसरे लोगों को इस पर बोलने की आज्ञा दें।

THE VICE-CHAIRMAN: You have raised your point of order. First of all, during the Zero Hour when the issues are raised by Members, no point of order is allowed. Number two^ you have shown your anxiety about the State subject being raised here. The hon. Chairman in his wisdom has permitted the Member., to raise the issue. Therefore, I am bound to call their names.

श्री सं : प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और अधिकार कुल्क वहाँ गन्ने की खेती करते हैं। वहाँ पर... (व्यवधान) मैं बहुत छोटा कहूँगा, यहाँ प्राध-प्राध घंटे तक भाषण होते हैं जीरो आवर में। मैंने यह तय किया था कि मैं किसी को इटरप्ट नहीं करूँगा। आप मुझ से देख रहे होंगे। ... (व्यवधान)

श्री स्वर प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : वे कह रहे हैं उत्तराखंड बनायेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम : उत्तराखंड बनायेंगे। हमने उत्तरांचल कहा है। फर्क शब्द का है। हमारी सरकार ने मांग की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अनेकों आवेदकों ने भारत सरकार से आবেदन किया है कि वहाँ के चीनी कारखानों को खोलने की उनकी

[श्री संजय प्रिय मोतम]

अनुप्राणित हो जाये। लगभग दो सौ चीनी कारखाने वहाँ लगाये जा सकते हैं। पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि यह अकेला उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। चीनी मिलों को लाइसेंस भारत सरकार देती है। इसलिए भारत सरकार इस मामले में इनबाधजन्य है। मैं यह आज कर रहा हूँ कि सारी 106 चीनी मिलें हैं जिसमें 40 निजी क्षेत्र में, 35 सरकारी क्षेत्र में और 31 सहकारी क्षेत्र की है और अन्य चीनी मिलों की भांग की जा रही है। वर्तमान सरकार ने इन 31 सहकारी क्षेत्र की जो मिलें और 35 सरकारी क्षेत्र की जो मिलें हैं, इन 66 मिलों में से 28 मिलों को निजी क्षेत्र के लोगों को बेचने का फैसला लिया है। मैं प्रदेश सरकार से मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश में माननीय अनेश्वर मिश्रा जी की पार्टी की सरकार है और मिश्रा जी सम्मानित सदस्य हैं और महान नेता हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह मिल क्यों बेचे जा रहे हैं? यह अवैधानिक कार्य है क्योंकि यह मिलें अभी नहीं हैं और अभी इनमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आई है। नम्बर दो, इन मिलों को बेचने से पहले जिस प्रबन्धन में यह काम कर रही है, उनको विश्वास में लेना चाहिये था। लेकिन 8 मिलों को बेचने का निर्णय दो महीने पहले और 20 मिलों को बेचने का निर्णय 19 जुलाई को लिया गया जबकि प्रबन्धकों को बँक इस निर्णय की पुष्टि के लिए 22 जुलाई को बुलाई गई। पहले उनको विश्वास में लेना चाहिये था। नम्बर तीन, इन 28 मिलों में ढाई लाख कर्मचारी काम करते हैं जो ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनका ग्रामदानी का कोई और जरिया नहीं है। 32 लाख किसान गला इन मिलों को देते हैं। इनको बेचने की जो कार्यवाही है वह अक्टूबर, नवम्बर माह में पूरी की जाएगी जबकि पेरार्ड का मौसम अक्टूबर में आरम्भ हो जाएगा। जब यह निर्णय ही नहीं होगा कि इन मिलों को कौन चलाएगा तो गला मिलों में नहीं आएगा

जिसके परिणाम-स्वरूप शुगर मिल नहीं चलेंगी और इससे किसान तथा मजदूर प्रभावित होंगे और चीनी की कमी हो जाएगी। इनमें से 22 मिलें ऐसी हैं जो सरकारी क्षेत्र की हैं। आज प्रदेश की सरकारों और केन्द्रीय सरकार में इस बात को होड़ लगी हुई है कि सरकारी क्षेत्र में जो मिलें हैं उनको निजी क्षेत्र में दे दिया जाए। आज ही हमारे सदन में शिङ्खुल कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा होने जा रही है। निजी क्षेत्र को हम दूसरे कारणों से प्रोत्साहन देते हैं ताकि कोटा, परमिट और लाइसेंस राज समाप्त हो और नये उद्यमियों को अवसर मिले और दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्दी हो और लोगों को जोड़ें सस्ती और अच्छी मिलें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र में जाने से कर्मचारियों के आरक्षण का क्या होगा और उसकी क्या गारंटी है? आज सरकारी क्षेत्र में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बर्तों हो जाते हैं। यह साफ जाहिर है कि जितनी कीमत बाजार में है उससे कम कीमत पर इन मिलों को बेचा जा रहा है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ (व्यवधान)

श्री संजय डालमिया (उत्तर प्रदेश) : यह असत्य बोल रहे हैं (व्यवधान) गलत बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री संजय प्रिय मोतम : मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि इन मिलों को न बेचा जाए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि प्राइवेट सेक्टर के लोग इन मिलों को चला सकते हैं तो फिर सरकारी और सहकारी क्षेत्र के लोग उन मिलों को क्यों नहीं चला सकते हैं? पहले इसका स्पष्टीकरण किया जाए। पहले उनसे सफाई मांगी जाए कि क्या तुम इन मिलों को चलाने में प्रक्षम हो? फिर मजदूरों से यह पूछा जाए कि क्या तुम इन मिलों को चला सकते हो। यदि वह सब मना कर दें और उन्हें प्रबन्धक मना कर दें, मजदूर मना करें सब आप निजी क्षेत्र में जाने की बात

सीने। (व्यवधान) मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करना चाहूंगा (व्यवधान) यह जो काम आप कर रहे हैं इससे किसानों पर बुरा असर पड़ेगा, मजदूरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं पुनः अपनी मांग को दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अध्यक्षवाद। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० नारायणसामी) : श्री राम गोपाल मादव जी।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप एसोसिएट करने के लिए खड़े हो सकते हैं (व्यवधान) आप इसके ऊपर नहीं बोल सकते हैं (व्यवधान) आप केवल एसोसिएट कर सकते हैं (व्यवधान)

श्री संजय डालमिया : आप गलत बात बोल रहे हैं (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० नारायणसामी) : आप बैठिये, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल मादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बहुत शफरसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मुझसे पूर्व जो माननीय सदस्य कह रहे थे वह इस सदन के अरिष्ट न केवल हम सभी संसद सदस्यों को बल्कि संपूर्ण देश की जनता को घुमराह करने का प्रयास गलत तथ्यों को रखकर कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनहित में... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : इस मामले को उठाने के पीछे परंपरा यह है कि... (व्यवधान)

SHRI SANJAY DALMIA: He can't not interrupt like this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): In our House, most, of the Members, in the name of

association, are disassociating on the subjects. This has been done in our House. (Interruptions) Mr. Gautam, you have had your say.

श्री राम गोपाल मादव : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मूलायम सिंह का नाम सुनते ही इनका विभागी सन्तुलन गड़बड़ा जाता है। इसलिए यह उस तरह की हरकतें करने लगते हैं जो कम से कम इस उच्च सदन में नहीं करनी चाहिए। मैं यह बताने जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित में उन मिलों में काम करने वाले मजदूरों के हित में यह निर्णय लिया है कि जो मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं उनको बेचा जाए और इन शर्तों पर ये मिलें बेची गई हैं या बेची जा रही हैं कि उनमें काम करने वाले किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और न छंटनी की जाएगी, जब इस शर्त पर यह हो रहा है तो यह कहना कि मजदूर बेकार हो जायेंगे, यह बेबुनियाद चीज है। मैं यह समझ रहा हूँ कि केवल राजनीतिक दृष्टि से यह मामला ये लोग उठा रहे हैं हालांकि ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का यह कदम उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की दिशा में एक कदम होगा और बड़ा काम करने वाले मजदूरों के हितों में भी होगा। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि जब यह मामला, ये एसोसिएट करने की बात नहीं थी, सब बात यह है कि मौलम साहब के मामले से अपने को डिस-एसोसिएट करने के लिए मैंने अपना नाम इसमें जोड़ा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Dalmia all of you are going to say the same-thing.

SHRI SANJAY DALMIA: No, Sir I am not going to repeat the same thing. I will tell you certain things which you would like to know. (Interruptions) I am not speaking to you Don't interrupt me

श्री जनार्दन यादव (बिहार) : क्या मजदूरों की मरवाते हैं... (व्यवधान) मजदूरों को क्यों मरवा दिया था... (व्यवधान) आप खड़े होकर क्यों उस समय मौल रहे थे? ... (व्यवधान)

श्री संजय डालमिया : मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि माननीय गौतम जी ने, उनको उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई में बहुत बड़ी चीज दिखती है और उनको लग रहा है कि यह जो शूगर मिलें हैं उनका जो निजीकरण हो रहा है उसमें वहाँ की जनता को नुकसान होगा। तो इनको यह पता होना चाहिए कि जब इनकी सरकार ने वहाँ पर अफ़्दान का निजीकरण करने का फैसला लिया था और उस वक़्त लिया था जबकि अफ़्दान फायदे में चल रही थी। अफ़्दान के जापानी कोलैबरेटर जो थे उनकी इच्छा के विरुद्ध इन्होंने अफ़्दान का निजीकरण करने का फैसला लिया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एम.आर.टी.पी. में लोगों को जाना पड़ा और वहाँ पर इसके खिलाफ़ स्ट्रेटो पड़ा क्योंकि यह गलत काम हो रहा था। इसका मतलब यह जो गलत काम करते हैं वे समझते हैं कि बाकी सरकारें भी गलत काम करती हैं। इनकी सरकार गलत काम कर रही थी वह एम.आर.टी.पी. ने रोक लगा दिया। ... (व्यवधान) पर अब यह निजीकरण का जो मामला है आपको मालूम है कि इनके घने चुनावी मुद्दों में निजीकरण के बारे में कहा गया है। आफ्टरमॉल जो स्टेट्स एंटरप्राइसेस हैं उनको जो नुकसान होता है... यह कौन देता है वह हमारी और आपकी जेब से निकलता है। हम, उत्तर प्रदेश की सरकार उन घाटे को मिलों का निजीकरण करके, जो हर साल घाटा होता है उस पैसे को बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वहाँ के पिछड़ों के लिए और गांवों के लिए खर्च करना चाहते हैं, परन्तु यह लोग उसमें बाधा पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सारी नीतियाँ यहीं हैं कि जहाँ भी बजटपैड के काम हों, जहाँ भी

अच्छे काम हों, वहाँ पर उनको रोक जाय। इसलिए यह फालतू के मुद्दे हाऊस में उठाते हैं और यहाँ सबन का समय बर्बाद करते हैं। मेरी यही निवेदन है कि यह निजीकरण का मामला उत्तर प्रदेश के हित में है और भारत सरकार की पालिसी के हित में है, इसलिए मेरी समझ में यह निजीकरण का मामला बहुत अच्छा है। हमें इसकी सराहना करनी चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, एक मिनट।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Another Member is there. You kindly take your seat.

SHRI SANJAY DALMLA: There is no point of order.

श्री ईश दास यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदैव संक्षेप में बोलता हूँ और इस विषय पर भी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ। हमारे भिन्न श्री संघ प्रिय गौतम जी ने शून्य काल में जो विषय उठाने के लिए दिया था, यह आपके भी समक्ष है और मेरे भी समक्ष है—

"Selling of sugar mills to private individuals by Uttar, Pradesh Government"

मैंने भी माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था। मैं समझ रहा था कि गौतम जी ने उत्तर प्रदेश की सरकार का जो निर्णय है—घाटे में चल रही बीनी मिलों को बेचने का, उनका समर्थन करने के लिए यह विषय जोरो धावर में उठाने के लिए दिया हुआ। मान्यवर, गौतम जी ने केवल अपने भाषण का एक अंश सही कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बीमार बीनी मिलों को रण बीनी मिलों को, जो घाटे में चल रही हैं—उनको बेचने का निर्णय किया है। यह अंश बिल्कुल सही है; लेकिन